



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2486]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 31, 2017/भाद्र 9, 1939

No. 2486]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 2017/BHADRA 9, 1939

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा-1 प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2017

का.आ.2834(अ).—जबकि, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, अपीलों, कर्नाटक राज्य के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में, उक्त मामले से संबंधित, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री एम. नारासम्पा, अधिवक्ता की विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति को गृह मंत्रालय की दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 3054 (अ) के तहत अधिसूचित किया था;

और जबकि, श्री एम. नारासम्पा को आबंटित किए गए कार्य की समीक्षा करने के पश्चात्, श्री एम. नारासम्पा की नियुक्ति को जारी न रखने का निर्णय लिया गया है;

अतः अब केन्द्र सरकार, विशेष लोक अभियोजक के रूप में श्री एम. नारासम्पा, अधिवक्ता की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2017

S.O.2834(E).—Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) had notified the appointment of Shri M. Narasappa, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the State of Karnataka vide Ministry of Home Affairs' notification No. S.O. 3054 (E) dated the 8th October, 2013;

And whereas, after review of the work allocated to Shri M. Narasappa, it has been decided that the appointment of Shri M. Narasappa may not be continued;

Now, therefore, the Central Government terminates the appointment of Shri M. Narasappa, Advocate as Special Public prosecutor with NIA with immediate effect.

[F.No. 11034/30/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2017

का. आ.2835(अ).—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से किसी जांच न्यायालय अथवा अपीलीय न्यायालय अथवा बिहार राज्य के भूभाग में विधि द्वारा स्थापित संशोधनात्मक न्यायालय के समक्ष मामलों के संचालन के लिए, एतद्वारा श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों के लिए बतौर विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2017

S.O.2835(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Akhileshwar Prasad Singh as Special Public Prosecutor (SPP) for conducting the cases on behalf of the National Investigation Agency before any trial court or appellate court or revisional court established by law in the territory of the State of Bihar for three years with effect from the date of publication of this notification.

[F.No. 11034/30/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.